Election Commission of India 3

NAME OF THE NEWSPAPER नवभारत टाइम्स DATE: 27 AUG 2012

वोटर से चैटिंग

अन्ना आंदोलन से हमारे नेताओं को पहली बार सोशल मीडिया का महत्व समझ में आया है। इसके ताजा उदाहरण हैं, गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जो गूगल प्लस के चैटिंग प्लैटफॉर्म -हैंगआउट पर 31 अगस्त को पूरे जोर-शोर से चैट करने उतर रहे हैं। भारतीय राजनीति के खिलाड़ियों के लिए यह एकदम नई पिच है और पहला मौका, जब कोई नेता अपने सरकारी निवास पर जनता की पंचायत लगाने के बजाय वर्चुअल दुनिया में लोगों से सीधे चैट करेगा। वैसे मौजूदा वक्त में अगर किसी नेता ने सोशल मीडिया की महिमा को पहचान कर उसका अपने प्रचार में इस्तेमाल किया है, तो वह नरेंद्र मोदी ही हैं। इससे पहले वे ट्विटर पर भी धूम मचा चुके हैं। हालांकि ट्विटर पर सबसे पहले शशि थरूर ने हमारा ध्यान खींचा था, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं मिला। अपने नेता को हमेशा खादी वस्त्रों में खड़े सेवक की तरह देखने के आकांक्षी कुछ भारतीय वोटरों को तब थरूर की वह अदा बर्दाश्त नहीं हुई थी और वे लगभग उल्टी करने लगे। पर मंत्रिमंडल से इनकी विदाई के बाद उमर अब्दुल्ला, सुषमा स्वराज, दिग्विजय सिंह, अजय माकन, मिलिंद देवड़ा, सचिन पायलट और करुणानिधि के अलावा पीएमओ तक का ट्विटर अकाउंट बन चुका है। और अब तो ममता बनर्जी ने भी फेसबुक पर एंट्री ले ली है। लेकिन अपने दिन भर के कार्यक्रम की जानकारी देने के अलावा ट्विटर का पूरा इस्तेमाल करने का आइडिया अभी कम ही नेताओं को आया है। अन्ना आंदोलन के वक्त जिस तरह सोशल मीडिया ने देश की जनता को एकजुट करने का काम किया, उसने नेताओं की नींद उड़ा दी। उसके बाद इस युवा ब्रिगेड को लुभाने का सबसे पहला चांस मिलने जा रहा है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि इसी साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं। अपने प्रचार के लिए वहां नेताओं और पार्टियों को अपनी डिजिटल रणनीति बनानी होगी, लेकिन सिर्फ इसके जरिए अपने साइबर फॉलोअर्स को असल वोटरों में तब्दील करना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इसका पूरा फायदा नेताओं को तभी मिल सकता है, जब वे अपनी पुरानी सोच को बदलें। वोटर तक पहुंचने और उसे लुभाने के दूसरे कई तरीके उन्हें पहले से आते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वोटरों से जुड़ने के लिए उन्हें नए जमाने की शर्तें पूरी करनी होंगी। दुनिया भर के नेता आज सोशल मीडिया की अहमियत पहचान रहे हैं, लेकिन कामयाब वही हो रहे हैं जो इसकी सबसे बड़ी शर्त यानी पारदर्शिता अपनाने की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। उन्हें यह समझना होगा कि उनके हर सही-गलत कदम पर ट्विटर और फेसबुक सवाल पूछेगा, जवाब मांगेगा और कुछ ही पलों में अपना रेफरेंडम सुना देगा। विधानसभा या संसद में हंगामा कर भले ही अपने विरोधियों को चुप कराया जा सकता है, लेकिन इस मंच पर तो उन्हें जवाब देने ही होंगे। यह समझना होगा कि यहां अलोकतांत्रिक, भेदभावपूर्ण और तानाशाह रवैये की न तो कोई इज्जत है और न जगह।

सोशल मीडिया पर नेताओं की एंट्री